भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .624

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

अंडमान में राष्ट्रीय राजमार्ग - 4 सड़क परियोजना

624. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान में एनएच-4 सड़क परियोजना में एक वर्ष से अधिक का विलंब हो गया है और आज तक 330.70 किलोमीटर की स्वीकृत लंबाई में से केवल 250 किलोमीटर ही पूरा किया जा सका है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार का विचार चरण-2, जिसमें 34.648 किलोमीटर की परियोजना शामिल है, के लिए लंबित वन विभाग की स्वीकृति के मुद्दे का समाधान किस प्रकार से करने का है जिसके कारण पहले ही 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत बढ़ चुकी है;

(ग) ईपीसी ठेकेदार के विरुद्ध आगे क्या कार्रवाई की गई है जिसके खराब प्रदर्शन के परिणामस्वरूप 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वृद्धि हुई है और विलंब के लिए उत्तरदायी होने के बावजूद केवल 10 करोड़ रुपये की शास्ति उस पर लगाई गई है;

(घ) परियोजना का मार्च 2024 की संशोधित समय-सीमा के अनुसार समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) प्रति दिन पांच लाख रुपये की विद्यमान शास्ति को ध्यान में रखते हुए, अपनी समय-सीमा का पालन करने में विफल रहने वाले ठेकेदारों पर लगाई जाने वाली अधिक प्रभावशाली शास्ति क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) आज की तिथि तक कुल 330.70 किलोमीटर लंबाई में से 291 किलोमीटर लंबाई पूरी हो चुकी है। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

i. वन मंजूरी में देरी
ii. स्टॉन एग्रिगेट की सीमित उपलब्धता
iii. कोविड-19 महामारी

iv. सीमित कार्य दिवस

v. संविदाकारों का खराब कार्य निष्पादन

(ख) पैकेज-III में 24 किलोमीटर (लगभग) और पैकेज-IV में 10 किलोमीटर का काम वन मंजूरी के कारण विलंबित हुआ। हालाँकि, चरण-II की मंजूरी नवंबर, 2023 में प्राप्त हुई है।

(ग) पैकेज-II, पैकेज-IV और पैकेज-VIII में संविदा करार के प्रावधानों के अनुसार लिक्विडिटी क्षति संविदाकार पर लगाई गई है। उर्पयुक्त के अलावा, मिडिल स्ट्रेट पर बड़ा पूल का पिछला संविदा समाप्त कर दिया गया है और परियोजना को फिर से मंजूरी दी गई है ।

(घ) मिडिल स्ट्रेट क्रीक पर बड़ा पूल के संबंध में संविदा के शेष कार्यों के लिए नए संविदाकार को नियुक्त किया गया है।

पैकेज-III (हम्फ्री ब्रिज और जरावा- II को छोड़कर बाराटांग से रंगत तक) को बंद कर दिया गया है और शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए परियोजना को दो भागों में विभाजित किया गया है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए दो नए संविदाकारों को नियुक्त किया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य शीघ्र पूरा हो जाए, निष्पादन एजेंसी द्वारा परियोजना की निरंतर निगरानी की जाती है।

(ङ) ईपीसी संविदा करार के तहत प्रावधान के अनुसार उन संविदाकारों पर जुर्माना लगाया गया है जो समय सीमा को पूरा करने में विफल रहे।

*****